Seventeenth Loksabha

>

Title: The Speaker made references to the passing away of Sir Anerood Jugnauth, former President and former Prime Minister of the Republic of Mauritius and; Dr. Kenneth David Buchizhya Kaunda, Founding Father and First President of the Republic of Zambia.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे इस सभा को दो महान अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों के निधन के संबंध में सूचित करना है।

श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ हमारे मित्र देश मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे छः बार मॉरीशस के प्रधानमंत्री भी रहे। वे भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य शिल्पकार थे। द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण भारत सरकार ने उन्हें नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से विभूषित किया था। उनका निधन 91 वर्ष की आयु में 3 जून, 2021 को मॉरीशस में हुआ।

डॉ. केनेथ डेविड बुचिजिया कौन्डा ज़ाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे सन् 1964 से सन् 1991 तक ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति रहे। ज़ाम्बिया के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी जी से विशेष प्रेरणा ली थी। उनका भारत से विशेष प्रेम था और उन्होंने भारत की अनेकों बार यात्राएं भी की थीं। वे पूरे अफ्रीका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। उनका निधन 97 वर्ष की आयु में 17 जून, 2021 को लुसाका, ज़ाम्बिया में हुआ।

यह सभा इन महान विभूतियों के निधन पर शोक व्यक्त करती है तथा उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। उनके सम्मान में अब सभा कुछ देर के लिए मौन रहेगी।

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

… (व्यवधान)

11.02 hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Gaurav Gogoi, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : यहां पर सभी मिनिस्टर्स बैठे हैं। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हैं। … (व्यवधान) यहां पर सारे मंत्री बैठे हुए हैं। …(व्यवधान) अधीर रंजन जी, यहां पर सभी मंत्री बैठे हैं, क्या वे आपको नहीं दिख रहे हैं? …(व्यवधान) आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आप तख्तियां लगाकर उनको भाषण नहीं देने दे रहे हैं, उनको वक्तव्य नहीं देने दे रहे हैं। …(व्यवधान) आप लोकतंत्र की परंपराओं को तोड़ रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी वेदना कहना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप अपनी सीटों पर विराजें। आप जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, आप अपनी सीटों पर जाइए, मैं सरकार से बात करूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, तो आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए, सामूहिक रूप से मिलिए। लेकिन सदन की कार्यवाही चले, सदन बाधित न हो, मेरा आप सभी से ऐसा आग्रह और निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए, ताकि हम हमारे मुद्दों और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाकर उनकी परेशानियों और तकलीफों को दूर कर सकें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

-

-

11.03 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 101, श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)

… (व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सोनकर ।

(Q. 101)

श्री विनोद कुमार सोनकर: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरा जो प्रश्न था, उसका उत्तर माननीय मंत्री जी के द्वारा बहुत विस्तार से दिया गया है, लेकिन जैसा कि

हम जानते हैं कि जब किसान जानकारी के अभाव में कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है, चूँकि कीटनाशक बहुत महंगे भी होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत अधिक क्षेत्र में बंजर हो जाती है।... (व्यवधान) साथ ही साथ कीटनाशक का आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से भूगर्भित जल भी दूषित होता है। हम लोग किसान हैं। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में सरकार बनी थी तो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने देश के किसानों की कृषि लागत को घटाने के लिए, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित ना हो, उसके लिए वर्ष 2014-15 में 'किसान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना' की शुरूआत की थी। (व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2014-15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बने थे, जिसके कारण से हम किसानों की कृषि भूमि के बारे में ठीक से जानकारी ले पाए कि किस कृषि भूमि में किसकी आवश्यकता है। किस कीटनाशक की कितनी आवयकता है और कितनी फसल हो सकती है?... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 'किसान सॉइल हेल्थ कार्ड' बनने के बाद क्या देश में कीटनाशक का उपयोग घटा है?... (व्यवधान) क्या इसको लेकर कोई अध्ययन कराया गया है या अध्ययन कराने पर सरकार विचार कर रही है, क्योंकि वर्ष 2017-18 में 15 करोड़ से ज्यादा 'किसान सॉइल हेल्थ कार्ड' बन चुके हैं?... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित प्रश्न किया है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजना के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का और उनको कार्ड पहुंचाने का काम किया है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड दो फेज़ में किसानों तक पहुंचे हैं। पहले फेज़ में लगभग 11 करोड़ और दूसरे फेज़ के अन्दर लगभग 11 करोड़ 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि किसानों के पास जो सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचे हैं, उनकी वजह से हमारे पास पूरे देश का डेटाबेस आ गया है कि

किसान के पास कौन सी जमीन है और उसकी वजह से हमने आने वाले समय के लिए प्लानिंग भी की है।... (व्यवधान)

दूसरा, इसके लिए वित्तीय प्रावधान के तहत उस समय लगभग 1326 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसके साथ ही आई.सी.ए.आर. के द्वारा एक स्टडी भी की गई थी और स्टडी से यह ज्ञात हुआ कि अगर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा उपयोग करनी चाहिए। इससे किसान जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी, उसका ही उपयोग करेगा।... (व्यवधान) इस तरह से उसकी स्टडी करने पर यह ज्ञात हुआ कि अगर वह इस आधार पर खेती करता है तो लगभग 15 से 20 प्रतिशत उर्वरकों की खपत कम हो सकती है। इसके साथ ही उत्पादन में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।... (व्यवधान) इस तरह से किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनी है। इसकी स्टडी भी की गई है। अगर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है और उसमें जिस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, उसी को लेकर खेती करता है तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही उस समय हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए ट्रेनिंग भी आयोजित की थी। उसके तहत लगभग 1,946 किसानों को ट्रेनिंग दी गई थी। इसके साथ ही हमने 5 लाख 50 हजार फील्ड डेमोंस्ट्रेशन भी किया था।... (व्यवधान) हमने 7,425 फार्मर मेले भी आयोजित किए थे। किसानों के लिए गांवों में एक लैब स्थापित होनी चाहिए, उसके लिए भी हमने लगभग 1532 गांवों में लैबोरेटरी के लिए 5 लाख रुपये एवेलेबल करवाए हैं। उसके तहत 1 लाख रुपये लैबोरेटरी स्थापित करने के लिए और बाकी 4 लाख रुपये भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से मिले हैं। आज किसान देश में जितने भी कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, वहां सॉइल टेस्ट करवा सकते हैं। आई.सी.ए.आर. के हमारे जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर भी टेस्टिंग हो सकती है। ... (व्यवधान) हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वे स्टेट गवर्नमेंट की हों या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी टेस्टिंग हो सकती है। ... (व्यवधान) इसकी वजह से आज भी किसान आकर कहते हैं कि इस टेस्टिंग की वजह से उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। मैं

समझता हूं कि आपने जिस विषय पर यह प्रश्न किया है, उसकी वजह से निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है।... (व्यवधान)

श्री भोला सिंह: धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आज सदन के सामने आया है और माननीय मंत्री जी ने इसका विस्तृत जवाब दिया है। ... (व्यवधान) मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में देश के किसानों को जैविक खेती की तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग ऐसे हैं, जो खाद और बीज के विक्रेता हैं, वे कुछ खतरनाक कीटनाशक किसानों को अनिवार्य रूप से देते हैं, जिनका दुष्प्रभाव फसलों पर पड़ता है। खासकर जो एन.सी.आर. है, मैं बुलंदशहर से आता हूं और बुलंदशहर एन.सी.आर. में है, वहां पर सब्जियों का ज्यादा उत्पादन होता है।... (व्यवधान) सब्जियों को जल्दी बढ़ाने के लिए उनमें घटिया किस्म के कीटनाशक उपयोग करते हैं और कुछ दुकानदार उनको जबर्दस्ती उसे देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे दुकानदारों पर किस तरीके से कार्रवाई करने की सरकार की योजना है? ... (व्यवधान)

दूसरा, सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, उसमें कितने किसानों का जैविक खेती का डेटा अभी तक सरकार के पास आया है? ... (व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो पेस्टिसाइड्स का उपयोग होता है और इस तरह से नकली पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने पर किस तरह से कार्रवाई होती है, मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के इंसपेक्टर्स होते हैं।... (व्यवधान) वे इंसपेक्टर्स वहां जाकर रेड करते हैं और अगर ऐसी कोई चीजे संज्ञान में आती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है और कानून में प्रावधान भी है।... (व्यवधान) आने वाले समय में, इस बारे में दो अन्य कानून हैं, जिनको राज्य सभा में इंट्रोड्यूस किया गया है और वे हमारी कमेटी के पास हैं। ... (व्यवधान)

आपने दूसरे विषय के रूप में जैविक खेती का जिक्र किया है। जैविक खेती को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार के बजट में अलग से प्रावधान किया। ... (व्यवधान) इसके लिए हमारा एक राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम है और परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत भी इस पर काम होता है।... (व्यवधान) इसके साथ ही, 'नमामि गंगे' के तहत गंगा के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ज़ोन्स घोषित किए गए हैं, जिनमें गंगा के किनारे पांच किलोमीटर क्षेत्र के अंदर जैविक खेती होती है। ... (व्यवधान) इसी तरह से भारतीय प्राकृतिक कृषि योजना के तहत भी इस कार्यक्रम को लिया गया है। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, उनको भी आर्गेनिक ज़ोन के तहत, कुछ स्थानों को चिन्हित करके यह काम किया जा रहा है।... (व्यवधान) आज देश के अंदर लगभग 38 लाख हेक्टेयर के अंदर आर्गेनिक खेती हो रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अगर किसान एक ग्रुप के अंदर जैविक खेती करते हैं, अगर वे दस किसानों तक का एक ग्रुप बनाकर जैविक खेती करते हैं और उनके पास कम से कम 20 हेक्टेयर जमीन होती है, तो सरकार द्वारा किसान को 50 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।... (व्यवधान) इसमें से 31 हजार रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में डाले जाते हैं। तीन साल के लिए यह प्रावधान है और बाकी 19 हजार रुपये उनको अलग-अलग ट्रेनिंग के लिए दिए जाते हैं, ताकि किसान जैविक खेती की ओर जाएं और जो पेस्टिसाइड्स की बड़ी समस्या हैं, उसका समाधान हो सके। ... (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए विशेष बजट देकर और हमने इसके लिए अलग से कार्यक्रम लेकर तथा किसानों को ट्रेनिंग देकर काम को आगे बढ़ाया है।

(Q. 102)

डॉ. आलोक कुमार सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तृत और स्पष्ट जानकारी के लिए मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देता हूं एवं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरा एक ही सप्लिमेंट्री प्रश्न है कि गोपालगंज में पीएमएफएमई के अंतर्गत

आने वाली इकाइयों के बारे में बताया जाए और गोपालगंज से जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में स्थिति बताई जाए। धन्वाद।... (व्यवधान)

श्री पशुपति कुमार पारस : अध्यक्ष महोदय, 38 जिलों में 35 उत्पादों की पहचान 'एक जिला, एक उत्पाद' के रूप में की गई है।...(व्यवधान) गोपालगंज में 68 सूक्ष्म तथा 2 समूह उद्योग इकाई इस वर्ष लगाने का लक्ष्य है।...(व्यवधान) गोपालगंज में अभी तक एक आवेदन का आवेदक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक जवाब दिया गया है।...(व्यवधान) 'एक जिला, एक उत्पाद' के तहत गोपालगंज को पपीता उत्पादन के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा पर चयन किया गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सेकेंड क्वेश्चन।

... (व्यवधान)

डॉ. आलोक कुमार सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि गोपालगंज में पीएमएफएमई के अंतर्गत कितनी इकाइयां हैं एवं गोपालगंज से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में बताया जाए।... (व्यवधान)

श्री पशुपति कुमार पारस : अध्यक्ष महोदय, पपीता उत्पादन के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा का चयन किया गया है। गोपालगंज में अभी तक एक आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक जमा किया गया है।... (व्यवधान) एक आवेदन पत्र।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ आई है। माननीय सदस्य महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। आप भी अपने-अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहां रखें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नारेबाजी और तख्तियों के लिए जनता ने आपको चुन कर यहां नहीं भेजा है। आप सभी अपनी जगह पर जाइए। देश में बाढ़ पर चर्चा हो

रही है।

… (<u>व्यवधान</u>)

(Q. 103)

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद और पूरे मराठवाड़ा में 14-15 अक्टूबर, 2020 को बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई थी।…(व्यवधान) जिसकी वजह से वहां के किसानों के पशुओं, खेती और फसलों का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ था।…(व्यवधान)

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 14-15 अक्टूबर, 2020 को बारिश होने के बाद केन्द्र से जो एक डेलिगेशन वहां पर सर्वे करने के लिए गया था। लगभग ढाई महीने बाद यानी 21 दिसम्बर, 2020 को वह टीम गई थी।…(व्यवधान) मैंने खुद चुनाव क्षेत्र में जाकर देखा है कि किसानों का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ था, तो उस टीम ने जो सर्वे किया था, उस सर्वे में वहां का नुकसान कितना प्रतिशत बताया गया है? मंत्री जी, कृपया इसका जवाब दें।…(व्यवधान)

श्री कैलाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि इन्होंने अपने क्षेत्र के नुकसान के बारे में जिक्र किया है।…(व्यवधान) भारत सरकार की योजना के तहत नुकसान होने पर फसल बीमा योजना के तहत वहां की राज्य सरकार से गिरदावरी की जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर उनको क्लेम दिया जाता है।…(व्यवधान) दूसरा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार की टीम वहां गई और वहां जो नुकसान हुआ, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो टीम वहां पर गई और उस टीम ने वहां का जो आकलन किया, उसके आधार पर हमारी जो उच्च स्तरीय कमेटी है, जिसमें हमारे गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी होते हैं, उन्होंने इसका फैसला करते हुए कर्नाटक, महाराष्ट्र और

राजस्थान के किसानों को एनडीआरएफ फंड से पैसे उपलब्ध करवा दिए हैं। इसके तहत महाराष्ट्र के लिए 701 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।...(व्यवधान)

वहीं राजस्थान में 113.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कर्नाटक के लिए भी 729.3 करोड़ रुपए एनडीआरएफ फण्ड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।... (व्यवधान) इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष इस प्रकार से आज किसानों के इतने महत्त्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हंगामा करके देश को क्या दिखाना चाहता है? ... (व्यवधान) एक तरफ प्रधानमंत्री जी चिन्ता कर रहे हैं कि देश के किसानों की इनकम बढ़े, किसानों की इनकम डबल हो, वहीं कृषि के इतने महत्त्वपूर्ण कानून बने हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप संक्षेप में उत्तर दीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री कैलाश चौधरी : जहाँ उत्पादन के कार्य की चिन्ता की जा रही है, वहीं ये लोग जिस तरह से हंगामा करके देश को किस तरह से दर्शाना चाहते हैं, ये सब देश के सामने है।... (व्यवधान)

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार ने आपको नुकसान का जो ज्ञापन सौंपा था, एनडीआरएफ से जो मदद माँगी थी, वह लगभग 3,721 करोड़ रुपए की थी। बड़ी मात्रा में नुकसान होने की वजह से यह जो मदद माँगी गई थी, वह एकदम वाज़िब थी। इसके बाद भी सरकार ने उत्तर में केवल यह कहा है कि 701 करोड़ रुपए उन्होंने वहाँ पर एलाऊ किया है।... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि 3,721 करोड़ रुपए का नुकसान होने के बावजूद केवल 701 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया, ऐसा उत्तर में कहा है, लेकिन अब तक 701 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार को नहीं मिले हैं।... (व्यवधान) इसलिए मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि 3,721 करोड़ रुपए के नुकसान के अगेंस्ट केवल 701 करोड़

रुपए क्यों दिए गए, ज्यादा धनराशि क्यों नहीं दी गई?... (व्यवधान) दूसरा प्रश्न यह है कि आप जो 701 करोड़ रुपए बता रहे हैं, वह भी अभी तक क्यों नहीं पहुँची है?... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता अपने क्षेत्र और राज्य की दृष्टि से वाज़िब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की नैचुरल क्लैमिटी होती है, तो उस समय एक प्रक्रिया बनी होती है, एक तो केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जाती है, किसानी का जो नुकसान होता है, वह फसल बीमा योजना के तहत कवर होता है और किसानी तथा अन्य प्रकार के जो नुकसान होते हैं, वे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत कवर होते हैं।... (व्यवधान)

जब महाराष्ट्र में क्लैमिटी आई तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी फायदा मिला और नैचुरल क्लैमिटी आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जो ज्ञापन केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया, तो केन्द्र सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयिक समिति बनाई, उस समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रवास किया और प्रवास करने के बाद उस समिति ने अपनी अनुशंसा की।... (व्यवधान) अनुशंसा करने के बाद जब वह गृह मंत्री जी के पास आई, तो गृह मंत्री जी ने महाराष्ट्र के लिए 701 करोड़ रुपए स्वीकृत किए।

इसके साथ ही साथ, आप देखेंगे तो खरीफ के लिए वर्ष 2020-21 और रबी के लिए वर्ष 2021 के दौरान महाराष्ट्र में 67.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया, जिसमें 11.43 लाख किसानों ने अपना दावा प्रस्तुत किया और फसल बीमा योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए का किसानों को लाभ दिया गया है।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को और प्रमुख रूप से विपक्षी सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि आज की कार्य-सूची में गाँव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा के लिए हैं।... (व्यवधान) अगर विपक्षी सदस्य किसानों के प्रति थोड़ा-सा भी दर्द रखते हैं, यदि वे किसानों के प्रति थोड़ी-सी भी

वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बनाकर अपने स्थानों पर बैठना चाहिए, इन प्रश्नों के माध्यम से उन्हें अपने विषय रखने चाहिए, उनको सरकार का जवाब सुनना चाहिए।... (व्यवधान) इस प्रकार से जो हो-हल्ला हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है, वह भी दृष्टिगोचर हो रहा है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कम्पीटिशन मत कीजिए, बल्कि जनता की समस्याओं को सदन में बोलने के लिए कम्पीटिशन करो।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप नारेबाजी में कम्पीटिशन कर रहे हैं। इसे जनता देख रही है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप जनता की समस्याएं उठाने के लिए कम्पीटिशन कीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>11.26 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Forty Five Minutes past Eleven of the Clock.

<u>11.45 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Forty Five Minutes past Eleven of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

माननीय सभापति : प्रश्न संख्या-104, श्री रामदास तडस जी।

… (व्यवधान)

11.45 ½ hrs

At this stage S/Shri Hibi Eden, Bhagwant Mann, Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(Q. 104)

श्री रामदास तडस: महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क के चयन की प्रक्रिया के विवरण प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (तीन) के गाइडलाइन 2019 में दिए गए हैं। पीएमजीएसवाई (तीन) के दिशा-निर्देश के अनुसार सड़क चयन प्रक्रिया के मापदंड पूर्ण न होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर लंबित हो जाते हैं। … (व्यवधान) जनता की भारी मांग के बावजूद अनेक प्रस्ताव केवल मापदंड पूर्ण न होने के कारण चयनित नहीं हो पाते हैं।… (व्यवधान) ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु सरकार की क्या योजना है? … (व्यवधान) सभी माननीय संसद सदस्य के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए क्या केंद्र सरकार इन मानदंडों में रियायत देने हेतु गाइडलाइन 2019 में बदलाव करने के लिए उचित कार्यवाही करेगी? धन्यवाद। … (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): सरकार का उद्देश्य उन गांवों को जोड़ने का है, जिन गांवों के रास्ते में या तो अस्पताल पड़ रहा हो या कोई विद्यालय पड़ रहा हो। ऐसी सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के

लिए वर्ष 2019 में थ्री फेजलाइन शुरू की गई थी। ... (व्यवधान) केंद्र में एक लाख 19 हजार किलोमीटर प्रमुख ग्रामीण लिंक रूट, 80 हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अवधि मार्च, 2025 तक के लिए निर्धारित की गई है। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य का प्रश्न जायज है।... (व्यवधान) उन्होंने महाराष्ट्र के संबंध में प्रश्न पूछा है कि वहां की सड़कें छोड़ी गई हैं। ... (व्यवधान) मैं उनको बताना चाहती हूं कि सर्वे करना, उनकी लागत तय करना प्रदेश सरकार का कार्य होता है। प्रदेश सरकार हमारे मानक के अनुसार भेजे तो हम उसे करने के लिए बाध्य होते हैं और करते भी हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किसानों से संबंधित, गांवों से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप इस चर्चा में शामिल हों और अपनी बातें रखें।

... (व्यवधान)

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 105 to 120

Unstarred Question Nos. 1151 to 1380)

(Page No. 39 to 863)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.50 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair)*

… (व्यवधान)

12.01 hrs

At this stage, Prof. Sougata Ray, Shri Hanuman Beniwal, Shri Hibi Eden, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came

and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)